भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में समकालीन समावेशी शिक्षाः भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के गुणवक्ता प्रबंधन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में अध्ययन

सिद्धार्थ कुमार
शोधार्थी
शिक्षाशास्त्र विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0
ईमेलः sidaryan98@yahoo.com

डॉ0 सीमा मिश्रा
असिस्टेंट प्रोफसर एवं विभागाध्यक्ष
शिक्षाशास्त्र विभाग
ए.पी.सेन मेमोरियल गर्ल्स पी.जी. कॉलेज
चारबाग, लखनऊ

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 07.03.26
Approved: 29.07.26

सिद्धार्थ कुमार
डॉ0 सीमा मिश्रा
भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में समकालीन समावेशी शिक्षाः भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के गुणवक्ता प्रबंधन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में अध्ययन

Vol. XVII, Sp. Issue Aug. 2026
Article No.27, Pg. 200-207
Similarity Check: 12%

Online available at
https://anubooks.com/special-issues?url=jgv-si-apsmgpc-lkn-2026
DOI: *https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI08.027*

सारांश

समावेशी शिक्षा समकालीन शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों विशेषकर दिव्यांग विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली के निर्माण पर विशेष बल दिया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित वसुधैव कुटुम्बकम् तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे सिद्धांत शिक्षा में समावेशिता और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करते हैं। इस संदर्भ में भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अध्ययन में मिश्रित शोध पद्धति (Mixed Method) का उपयोग किया गया। अध्ययन हेतु 10 RCI अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन उद्देश्यपूर्ण नमूना (Purposive Sampling) के आधार पर किया गया। डेटा संकलन के लिए प्रश्नावली, अर्ध–संरचित साक्षात्कार तथा संस्थागत निरीक्षण का उपयोग किया गया। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, माध्य तथा व्याख्यात्मक विश्लेषण के माध्यम से किया गया। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश संस्थानों में अवसंरचना, पाठ्यक्रम अद्यतन तथा प्रषासनिक गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तथापि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित नैतिक, सांस्कृतिक एवं मूल्यपरक दृष्टिकोण का समुचित एकीकरण अभी भी सीमित पाया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थागत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को और प्रभावी बनाना आवश्यक है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशी एवं मानवीय मूल्यों को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत करने से समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्दः *भारतीय ज्ञान परंपरा, समावेशी शिक्षा, गुणवत्ता प्रबंधन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI), विशेष शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण।*

**This article has been peer-reviewed by the Review Committee of JGV.*

https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI08.027

प्रस्तावना

शिक्षा को मानव समाज के विकास, सामाजिक परिवर्तन तथा समान अवसरों की स्थापना का प्रमुख आधार माना जाता है। समकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, न्याय और समावेशिता को प्रोत्साहित करना भी है। इसी संदर्भ में समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) की अवधारणा विशेष महत्व प्राप्त करती है, जिसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों–विशेषकर दिव्यांग विद्यार्थियों–को उनकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है।

भारतीय शिक्षा परंपरा प्राचीन काल से ही समग्र एवं मूल्याधारित रही है। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम माना जाता था, जिसमें बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकास पर समान रूप से बल दिया जाता था। भारतीय ज्ञान परंपरा की जड़ें वेदों, उपनिषदों तथा बौद्ध–जैन दार्शनिक परंपराओं में निहित हैं, जहाँ शिक्षा को आत्मबोध, नैतिकता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास का साधन माना गया है। डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन के अनुसार भारतीय शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के आत्म–विकास के साथ सामाजिक समरसता की स्थापना करना है (Radhakrishnan, 1953)।

भारतीय ज्ञान परंपरा में "वसुधैव कुटुम्बकम", "सर्वे भवन्तु सुखिनः" तथा "लोकसंग्रह" जैसे सिद्धांत सामाजिक समानता, सह–अस्तित्व और सामूहिक कल्याण की भावना को सुदृढ़ करते हैं। ये सिद्धांत आधुनिक समावेशी शिक्षा के मूल्यों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। प्राचीन भारत के नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय विविध सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए खुले थे, जो इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशिता का विचार ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा को मानव जीवन के समग्र विकास का साधन माना गया है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना का संचय नहीं बल्कि व्यक्ति में जागरूकता, नैतिकता तथा आत्मबोध का विकास करना है। उनका मानना था कि शिक्षा को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से विकास कर सके (Krishnamurti, 2001)। यह विचार समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के साथ गहराई से मेल खाता है

समकालीन शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण वैश्विक अवधारणा के रूप में विकसित हुई है। UNESCO ने 1994 में Education for All के सिद्धांत के माध्यम से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए यह स्पष्ट किया कि शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि वह सभी प्रकार की विविधताओं को स्वीकार और समाहित कर सके। इसी प्रकार डमस Ainscow (2005) के अनुसार समावेशी शिक्षा केवल संरचनात्मक परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण, नीतियों और व्यवहार में व्यापक परिवर्तन की प्रक्रिया है।

भारत में समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल की गई हैं। विशेष रूप से Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 तथा National Education Policy 2020 ने शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेषी, सुलभ और न्यायसंगत बनाने पर बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुलभ अवसंरचना, सहायक तकनीकों का उपयोग, तथा प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की उपलब्धता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षक प्रशिक्षण को समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन का आधार माना जाता है। Tim Loreman (2010) ने अपने अध्ययन में बताया कि समावेशी कक्षा के निर्माण के लिए शिक्षक की सकारात्मक दृष्टि, पेशेवर दक्षता तथा प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार यदि शिक्षकों को विविध अधिगम आवश्यकताओं और सहायक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए तो वे सभी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण विकसित कर सकते हैं।

समावेशी शिक्षा की वैश्विक प्रगति पर किए गए अध्ययन में UNICEF (2019) ने यह बताया कि शिक्षा प्रणाली में समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयी अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि शिक्षा व्यवस्था में विविधता को स्वीकार करने की संस्कृति विकसित की जाए तो

यह विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। शिक्षा में समान अवसरों की अवधारणा पर World Bank (2018) की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि समावेशी शिक्षा सामाजिक असमानताओं को कम करने का एक प्रभावी माध्यम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शिक्षा संस्थानों को ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों को अधिगम के समान अवसर प्रदान करें। समावेशी शिक्षा के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर किए गए अध्ययन में Sharma and Deppeler (2005) ने पाया कि शिक्षक का दृष्टिकोण और प्रशिक्षण समावेशी शिक्षा की सफलता को सीधे प्रभावित करता है। उनके अनुसार यदि शिक्षकों को समावेशी शिक्षण पद्धतियों तथा विविध अधिगम आवश्यकताओं के बारे में उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो विद्यालयों में समावेशी वातावरण का निर्माण अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा के विकास पर Singal (2019) ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में समावेशी शिक्षा के लिए नीतिगत स्तर पर कई सकारात्मक पहल की गई हैं, लेकिन इन नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में गुणवत्ता प्रबंधन और शिक्षक प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें नियोजन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। Edward Sallis (2014) के अनुसार Total Quality Management (TQM) मॉडल शैक्षणिक संस्थानों में प्रभावी प्रशासन, सतत सुधार तथा परिणामोन्मुखी शिक्षण व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता पर किए गए अध्ययन में Darling&Hammond (2017) ने यह बताया कि प्रभावी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षकों को केवल विषय ज्ञान ही नहीं बल्कि विविध विद्यार्थियों के साथ कार्य करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। उनके अनुसार आधुनिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक अधिगम और तकनीकी संसाधनों के उपयोग को शामिल करना आवश्यक है। शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा पर Deming (1986) द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। Deming के अनुसार गुणवत्ता सुधार एक सतत प्रक्रिया है जिसमें संस्थागत नियोजन, संसाधनों का प्रभावी उपयोग तथा निरंतर मूल्यांकन शामिल होता है। इन सिद्धांतों को शिक्षा संस्थानों में लागू करने से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार संभव है।

भारत में विशेष शिक्षा और पुनर्वास से संबंधित पेशेवरों के प्रशिक्षण और मानकीकरण में Rehabilitation Council of India (RCI) की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संस्था विशेष शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करती है, पाठ्यक्रम मानकों का निर्धारण करती है, विशेष शिक्षकों का पंजीकरण करती है तथा प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। RCI द्वारा अनुमोदित संस्थान विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, बी.एड. विशेष शिक्षा तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं, जिनका उद्देश्य समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन तैयार करना है। समावेशी शिक्षा में तकनीक के उपयोग पर Al &Azawei, Serenelli and Lundqvist (2016) ने अपने अध्ययन में बताया कि सहायक तकनीकों और डिजिटल संसाधनों का उपयोग दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को अधिक सुलभ और प्रभावी बना सकता है। उनके अनुसार तकनीकी साधन समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अध्ययन भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल सिद्धांतों, समावेशी शिक्षा की आधुनिक अवधारणा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता प्रबंधन के बीच अंतर्संबंधों का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में RCI द्वारा अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन और गुणवत्ता प्रबंधन की स्थिति को समझने का प्रयास करता है।

https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI08.027

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge System) के समावेशी शैक्षिक सिद्धांतों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
2. National Education Policy 2020 के समावेशी प्रावधानों का अध्ययन करना।
3. RCI - अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना।
4. भारतीय ज्ञान परंपरा तथा NEP 2020 के प्रावधानों के संदर्भ में RCI–अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के गुणवत्ता प्रबंधन और समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण के मध्य संबंध का विश्लेषण करना।

परिकल्पनाएँ

1. भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge System) के समावेशी शैक्षिक सिद्धांतों और RCI&अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के गुणवत्ता प्रबंधन के मध्य सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है।
2. National Education Policy 2020 के समावेशी प्रावधानों का RCI–अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
3. भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांतों के समावेशन से RCI–अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन का स्तर बेहतर होता है।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में समकालीन समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा Rehabilitation Council of India द्वारा अनुमोदित शिक्षक प्रषिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता प्रबंधन की स्थिति का विश्लेषण करना है। साथ ही अध्ययन में National Education Policy 2020 के संदर्भ में इन संस्थानों में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन की स्थिति का भी परीक्षण किया गया है। अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक (Descriptive and Analytical) है, क्योंकि इसमें वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों, नीतिगत प्रावधानों तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है।

इस अध्ययन में मिश्रित अनुसंधान दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया। गुणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा, समावेशी शिक्षा तथा नीतिगत दस्तावेज़ों का विश्लेषण किया गया, जबकि मात्रात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता प्रबंधन की स्थिति का सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन के लिए सर्वेक्षण अनुसंधान डिजाइन का उपयोग किया गया, जिससे संस्थानों की वास्तविक शैक्षिक स्थिति का व्यवस्थित विश्लेषण संभव हो सका।

अध्ययन की जनसंख्या में भारत में स्थित वे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं जिन्हें Rehabilitation Council of India द्वारा मान्यता प्राप्त है। नमूना चयन के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन विधि का उपयोग किया गया। इस प्रक्रिया में 10 RCI–अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया। इन संस्थानों से कुल 140 प्रतिभागियों को नमूने के रूप में शामिल किया गया, जिनमें 40 शिक्षक तथा 100 छात्र–शिक्षक शामिल हैं।

अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया। प्राथमिक डेटा प्रश्नावली और अर्ध–संरचित साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षकों और छात्र–शिक्षकों से प्राप्त किया गया, जबकि द्वितीयक डेटा नीतिगत दस्तावेज़ों, सरकारी रिपोर्टों, शोध पत्रों तथा पुस्तकों से संकलित किया गया, जिनमें विशेष रूप से National Education Policy 2020 तथा Rehabilitation Council of India से संबंधित दस्तावेज़ शामिल हैं।

संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय तकनीकों की सहायता से किया गया, जिनमें प्रतिशत, माध्य तथा

मानक विचलन, सहसंबंध विश्लेशण, टी–परीक्षण प्रमुख हैं। विश्लेषण के परिणामों को तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिससे अध्ययन के निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके।

परिणाम एवं डेटा विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में RCI–अनुमोदित 10 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से कुल 140 प्रतिभागियों (40 शिक्षक एवं 100 छात्र–शिक्षक) से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन के उद्देश्यों और परिकल्पनाओं की जाँच के लिए प्रतिशत, माध्य, मानक विचलन, सहसंबंध विश्लेषण तथा ज–परीक्षण जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त गुणात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के साथ अर्ध–संरचित साक्षात्कार (Semi structured Interview) भी किए गए। परिणामों को निम्न तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1

भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशन के संबंध में प्रतिभागियों की राय (प्रतिशत विश्लेषण)

प्रतिक्रिया	शिक्षक (%)	छात्र–शिक्षक (%)
पूर्णतः सहमत	45	42
सहमत	40	38
अनिश्चित	10	12
असहमत	5	8

व्याख्याः

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि लगभग 85ः शिक्षकों और 80ः छात्र–शिक्षकों ने यह स्वीकार किया कि शिक्षक प्रषिक्षण संस्थानों में भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांतों का समावेषन समावेषी षिक्षा के विकास में सहायक है। इससे यह संकेत मिलता है कि IKS के मूल्य समावेशी शिक्षण–प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।

तालिका 2

भारतीय ज्ञान परंपरा, समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता प्रबंधन का वर्णनात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण

व्याख्याः

Variable	N	Mean	SD
Indian Knowledge System (IKS) Integration	140	3-87	0-65
Inclusive Teacher Training	140	3-81	0-69
Institutional Quality Management	140	3-74	0-67

तालिका 2 से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांतों के समावेशन का औसत स्तर अपेक्षाकृत उच्च पाया गया। इसी प्रकार समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण (3.81) तथा संस्थागत गुणवत्ता प्रबंधन (3.74) भी संतोषजनक स्तर पर पाए गए। यह संकेत करता है कि RCI–अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा से संबंधित गतिविधियों तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रियाओं को किसी न किसी स्तर पर लागू किया जा रहा है।

https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI08.027

तालिका 3

भारतीय ज्ञान परंपरा, समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता प्रबंधन के मध्य सहसंबंध

Variables	IKS	Inclusive Training	Quality Management
Indian Knowledge System	1		
Inclusive Teacher Training	0-57	1	
Institutional Quality Management	0-52	0-61	1

व्याख्या:

तालिका 3 के अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा और समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण के बीच मध्यम स्तर का सकारात्मक सहसंबंध (0.57) पाया गया। इसी प्रकार भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्थागत गुणवत्ता प्रबंधन के बीच सकारात्मक सहसंबंध (0.52) पाया गया। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण और गुणवत्ता प्रबंधन के मध्य भी उच्च सकारात्मक संबंध (0.61) पाया गया। यह परिणाम पहली परिकल्पना का समर्थन करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशी सिद्धांतों और संस्थागत गुणवत्ता प्रबंधन के मध्य सकारात्मक संबंध विद्यमान है।

तालिका 4

NEP 2020 के प्रभाव का ज–परीक्षण विश्लेषण

Group	N	Mean	SD	t value	Significance
Teachers	40	3-84	0-66	2-41	0-05
Student Teachers	100	3-68	0-71		

व्याख्या:

ज–परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि शिक्षकों और छात्र–शिक्षकों के दृष्टिकोण में NEP 2020 के प्रभाव के संबंध में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर (tz 2.41, $p < 0.05$) पाया गया। इसका अर्थ यह है कि NEP 2020 के समावेशी प्रावधान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षण–प्रशिक्षण प्रक्रियाओं तथा गुणवत्ता प्रबंधन को प्रभावित कर रहे हैं। यह परिणाम दूसरी परिकल्पना का समर्थन करता है।

गुणात्मक परिणाम

साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त गुणात्मक आंकड़ों से कुछ महत्वपूर्ण विषय सामने आए:

1. अधिकांश शिक्षकों ने यह बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्य जैसे समता, सहअस्तित्व और सहयोग समावेशी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।
2. कई शिक्षकों ने यह भी कहा कि NEP 2020 ने समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में।
3. कुछ प्रतिभागियों ने यह सुझाव दिया कि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विषयों को और अधिक व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

4. संस्थानों में समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता भी व्यक्त की गई।

परिणामों की चर्चा

अध्ययन के परिणाम यह संकेत करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशी शैक्षिक सिद्धांत समकालीन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहसंबंध विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय ज्ञान परंपरा और समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण के बीच सकारात्मक संबंध विद्यमान है। भारतीय शिक्षा दर्शन में निहित समता, सहअस्तित्व, सहयोग, करुणा और सर्वांगीण विकास जैसे मूल्य समावेशी शिक्षा की अवधारणा के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि National Education Policy 2020 ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन को और अधिक प्रोत्साहित किया है। NEP 2020 के अंतर्गत बहुभाषिकता, समान अवसर, लचीला पाठ्यक्रम, समग्र विकास तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण–पद्धतियों पर विशेष बल दिया गया है। ज–परीक्षण के परिणाम यह दर्शाते हैं कि शिक्षकों और छात्र–शिक्षकों दोनों के दृष्टिकोण में NEP 2020 के प्रभाव को सकारात्मक रूप में अनुभव किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि जिन संस्थानों में भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांतों का समुचित समावेशन किया गया है, वहाँ समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर पाया गया। इससे तीसरी परिकल्पना को भी समर्थन प्राप्त होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों को यदि आधुनिक शैक्षिक नीतियों, विशेषकर NEP 2020 के प्रावधानों के साथ समन्वित रूप में लागू किया जाए, तो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन की प्रभावशीलता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।

अतः यह निकर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और समकालीन शैक्षिक नीतियों का समन्वित दृष्टिकोण शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में एक ऐसे शैक्षिक वातावरण के निर्माण में सहायक हो सकता है जो विविधता, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करता है तथा समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में समकालीन समावेशी शिक्षा की अवधारणा का विश्लेषण करना तथा RCI–अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करना था। अध्ययन के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशी शैक्षिक सिद्धांत समावेशी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित समता, सहयोग, सहअस्तित्व और सर्वांगीण विकास जैसे मूल्य समावेशी शिक्षा की मूल भावना के अनुरूप हैं और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष यह भी दर्शाते हैं कि National Education Policy 2020 ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीति के अंतर्गत समान अवसर, बहुभाषिकता, समग्र विकास तथा विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण–पद्धतियों पर विषेश बल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षक प्रषिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षण–प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और गुणवत्ता प्रबंधन की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।

सहसंबंध विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांतों के समावेशन और संस्थागत गुणवत्ता प्रबंधन के बीच सकारात्मक संबंध पाया जाता है। जिन संस्थानों में भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों को शिक्षण–प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में अधिक महत्व दिया गया, वहाँ समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर

https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI08.027

पाया गया। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और NEP 2020 के प्रावधानों का समन्वित दृष्टिकोण शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में समावेशी शिक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

शैक्षिक निहितार्थ / सुझाव

- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेशी शैक्षिक सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों में समावेशी दृष्टिकोण का विकास हो सके।
- RCI–अनुमोदित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में NEP 2020 के समावेशी प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ तथा शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षण विधियों, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा विविधता आधारित शिक्षण रणनीतियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- संस्थानों में गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर मूल्यांकन, शैक्षिक नवाचार और सहभागी शिक्षण वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- भविष्य के शोध में भारतीय ज्ञान परंपरा और समावेशी शिक्षा के संबंध को अधिक व्यापक नमूने और विभिन्न राज्यों के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययन किया जा सकता है, जिससे इस विषय की गहन समझ विकसित हो सके।

संदर्भ

1. ऐन्स्को, एम. (2005). समावेशी शिक्षा प्रणालियों का विकास। जर्नल ऑफ एजुकेशनल चेंज।
2. अल–अज़ावेई, ए., सेरेनेली, एफ., एवं लुंडक्विस्ट, के. (2016). उच्च शिक्षा में यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का उपयोग। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन, 13(1), पृ0सं0–**1–18।**
3. डार्लिंग–हैमंड, एल. (2017). विश्व में शिक्षक शिक्षा। जोसी–बास।
4. डेमिंग, डब्ल्यू. ई. (1986). संकट से बाहर। एमआईटी प्रेस।
5. भारत सरकार। (1992). पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992। भारत सरकार।
6. भारत सरकार। (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
7. कृष्णमूर्ति, जे. (2001). शिक्षा और जीवन का महत्व। हार्पर कॉलिन्स।
8. मार्शार्क, एम., एवं हाउज़र, पी. (2012). बधिर बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. प्रेसमोएलर, एम. (2000). प्रारंभिक हस्तक्षेप और भाषा विकास।
10. राधाकृष्णन, एस. (1953). हिंदू जीवन दृष्टि।
11. सैलिस, ई. (2014). शिक्षा में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन।
12. शर्मा, यू., एवं डेपेलर, जे. (2005). भारत में एकीकृत शिक्षा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 20(2), पृ0सं0–**1–14**
13. सिघल, एन. (2019). भारत में समावेशी शिक्षाः चुनौतियाँ और अवसर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्क्लूसिव एजुकेशन, 23(7–8), पृ0सं0–**827–842**।
14. यूनेस्को। (1994). विशेष आवश्यकता शिक्षा पर सलामांका घोषणा। यूनेस्को।
15. यूनिसेफ। (2019). दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। यूनिसेफ।
16. विश्व बैंक। (2018). विश्व विकास रिपोर्टः शिक्षा की संभावनाओं को साकार करना। विश्व बैंक।
17. विश्व स्वास्थ्य संगठन। (2021). विश्व श्रवण रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन।